मप्र बोर्ड के सरकारी स्कूलों की कक्षा 9वीं व 11वीं का परिणाम 15 मई को

भोपाल (नईदुनिया प्रतिनिधि)। मप्र बोर्ड से संबद्ध सरकारी स्कूलों का परीक्षा परिणाम 15 मई को घोषित किया जाएगा। इस संबंध में लोक शिक्षण संचालनालय (डीपीआइ) ने आदेश जारी किए हैं कि कोरोना संक्रमण की स्थिति को देखते हुए 30 अप्रैल को घोषित किया जाने वाला परीक्षा परिणाम अब 15 मई तक घोषित किया जाएगा। सभी संभागीय संयुक्त संचालकों व जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश जारी किए गए हैं कि परीक्षा परिणाम संबंधी जानकारी विमर्श पोर्टल पर 15 मई तक दर्ज करवाएं। बता दें, कि मप्र स्कूल शिक्षा विभाग ने कुछ दिन पहले आदेश जारी कर नौवीं व 11वीं की वार्षिक परीक्षा को निरस्त कर रिवीजन टेस्ट और छमाही परीक्षा के आधार पर मूल्यांकन करते हुए रिजल्ट तैयार करने के निर्देश दिए हैं।

विश्वविद्यालयों की परीक्षाएं व प्रवेश प्रक्रिया आगे बढ़ाने की तैयारी

नई दिल्ली (ब्यूरो)। कोरोना की दूसरी लहर को देखते हुए विवि व कॉलेजों की आगामी सभी प्रस्तावित परीक्षाओं और प्रवेश प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की तैयारी हो रही है। यूजीसी जल्द ही गाइडलाइन जारी करेगा। उच्च शिक्षण संस्थानों ने ज्यादा से ज्यादा कोर्सों को आनलाइन या फिर दूरस्थ शिक्षा के माध्यमों से संचालित करने का फैसला किया है।

Badri Gautam

शिक्षकों ने कहा, डर और चिंता में जी रहे हैं बच्चे, मंडल नहीं ले पा रहा ठोस निर्णय

बच्चों में असमंजस की स्थिति दूर करने मंडल पर दबाव

भोपाल ■ राज न्यूज नेटवर्क

बोर्ड परीक्षाओं को लेकर आगे क्या होना है। मंडल पर तत्काल इस विषय में निर्णय लेने के लिए शिक्षकों ने दबाव बनाया है। टीचरों का कहना है कि बच्ची लगातार तनाव और डर के बीच असमंजस के माहौल में जी रहे हैं। शिक्षकों के अनुसार मध्यप्रदेश में हाई स्कूल एवं हायर सेकंडरी परीक्षाओं को लेकर आज भी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा कोई अधिकृत निर्णय न लेने के कारण छात्रों में परीक्षा को लेकर एक भ्रम की स्थिति पैदा हो रही है। वही सोशल मीडिया और विभिन्न व्हाट्सएप ग्रुप पर चल रही अनाधिकृत जानकारी ने छात्रों को पूरी तरीके से उलझा दिया है। छात्र यह समझ नहीं पा रहे हैं कि उन्हें परीक्षा की तैयारी करना चाहिए या जनरल प्रमोशन मान कर अगली कक्षा में प्रवेश की प्लानिंग करनी चाहिए।

शिक्षकों का कहना है कि कोरोना संक्रमण को देखते हुए सीबीएसई बोर्ड ने अपनी कक्षा दसवीं की परीक्षा को निरस्त कर दिया है। देश के अन्य शिक्षा बोर्डों ने भी तत्काल निर्णय लेते हुए अपने अपने प्रदेश की परीक्षाओं को निरस्त कर दिया है लेकिन माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्यप्रदेश भोपाल द्वारा अभी तक कोई निर्णय न लेने से शिक्षक एवं छात्र दोनों ही असमंजस की स्थिति में है। छात्र बार.बार माध्यमिक शिक्षा मंडल की हेल्पलाइन नम्बर पर संपर्क कर रहे हैं लेकिन उन्हें कोई संतोषजनक जवाब प्राप्त नहीं हो रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में भी अब तेजी से पैर पसार रहे इस कोरोना संक्रमण के कारण छात्रों एवं उनके अभिभावकों में भय की स्थिति बनी हुई है। अभिभावक अपने बच्चों के भविष्य को लेकर चिंतित है। परीक्षाओं की स्थिति स्पष्ट ना होने के कारण छात्र भी पूर्ण मनोयोग से अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पा रहे हैं। छात्रों ने चर्चा में बताया कि परीक्षाओं की स्थिति अब तक स्पष्ट ना होने से उनका पढ़ाई में मन नहीं लग पा रहा है और वह अपने भविष्य को लेकर लगातार चिंतित हैं।

यह समझ से परे है कि जब केंद्रीय बोर्ड एवं अन्य प्रदेशों के शिक्षा बोर्ड ने समय पर अपना स्पष्ट निर्णय ले लिया है। ऐसी स्थित मैं माध्यमिक शिक्षा मंडल क्यों आज तक अ अनिर्णय की स्थिति में है। इस असमंजस की स्थिति के चलते प्रदेश के लाखों छात्र मानसिक दबाव एवं पीड़ा से गुजर रहे हैं। माध्यमिक शिक्षा मंडल के संबंधित अधिकारियों को जल्द से जल्द अपनी कार्य योजना परीक्षाओं को लेकर अपनी रणनीति की स्पष्ट घोषणा करनी चाहिए ताकि छात्रों में व्याप्त भय एवं दबाव दूर हो सके और छात्र तनावमुक्त होकर अपने भविष्य की प्लानिंग कर सकें।

विद्यार्थियों में चिंता और भ्रम को दूर करें मंडल

मध्यप्रदेश शासकीय अध्यापक संघ के वरिष्ठ पदाधिकारी खुर्शीद अहमद खान का कहना है कि परीक्षाओं को लेकर विद्यार्थियों में जो भ्रम की एवं चिंता की स्थिति है उसको मंडल तत्काल दूर करें। क्योंकि जब सीबीएसई बोर्ड सहित अन्य राज्यों ने निर्णय ले लिया है तो आखिर मध्य प्रदेश सरकार को भी तत्काल इस विषय में फैसला करना चाहिए। खुर्शीद का कहना है कि आज प्रदेश में बच्चे ही नहीं शिक्षक भी गंभीर चिंताओं के दौर से गुजर रहे हैं। सरकार इस विषय में तत्काल ठोस निर्णय ले।

पूरे प्रदेश में बच्चों को मंडल के निर्णय की प्रतीक्षा

शासकीय अध्यापक संघ के पदाधिकारी राजकुमार शर्मा का कहना है कि पूरे प्रदेश के बच्चे और शिक्षक परीक्षाओं के निर्णय पर टकटकी लगाए हुए हैं। उन्होंने कहा है कि इस समय बच्चों के बीच एक ही चर्चा है कि आखिर परीक्षाओं का क्या होगा। शर्मा का कहना है कि मंडल को तत्काल निर्णय लेते हुए स्थिति स्पष्ट करना चाहिए। इसके अलावा राज्य सरकार को बिना देर किए हुए शिक्षकों के लिए कोरूणा योग्य योजना लागू करना चाहिए।

Badri Gautam

कोरोना की दूसरी लहर में बच्चों की अध्यापन गुणवत्ता पर रहेगा शिक्षक संघ का फोकस

वर्ष भर चलने वाले स्वर्ण जयंती समारोह में निर्णय अक्टूबर में स्मारिका का विमोचन

भोपाल ■ राज न्यूज नेटवर्क

अपनी स्थापना के 50 साल पूरे करने पर मध्य प्रदेश शिक्षक संघ स्वर्ण जयंती समारोह मना रहा है। संगठन का दावा है कि मौजूदा वर्ष में लगातार शिक्षा के गुणात्मक विकास की दिशा में सफल कार्यक्रम आयोजित होंगे। विद्यालयों की दिशा और दशा बदलने के लिए संगठन विशेषज्ञ शिक्षकों के माध्यम से शासन तक सुझाव भेजेगा और उन पर अमल करवाने की कोशिश करेगा।

महामारी संक्रमण की दूसरी लहर में स्कूली बच्चों का गुणात्मक विकास करने के लिए संगठन द्वारा शीघ्र ही पूरे राज्य में यह कार्यक्रम ऑनलाइन शुरू किये जा रहे है। कोरोना की बढ़ती रफ्तार को देखते हुए यह व्यवस्था की गई है।

संघ पदाधिकारियों द्वारा कहा गया है कि ईर्ष्या दोष से परे सामूहिकता की भावना को लेकर, व्यक्तिगत हितों को दरकिनार कर कार्य करने वाले समर्पित कार्यकर्ताओं का यह संगठन है। अपने अधिकारों की रक्षा के साथ कर्तव्यबोध की भावना से संगठन को चलाना, प्रसन्न भाव से बच्चों के कल्याण के बारे में विचार करना यही शिक्षक संघ का कार्य होता है। जिसे शिक्षक संघ ने पूरा करने का सतत प्रयास किया है।

प्रत्येक शिक्षक राष्ट्रीय पुनर्निर्माण के ध्येय को ध्यान में रखकर वह अध्यापन कार्य करें, उसे विचार करना चाहिए कि मैंने अपनी पूरी क्षमता का उपयोग कर अपना आज का शिक्षण कार्य किया क्या क्योंकि प्रत्येक बात का रास्ता शिक्षा से होकर ही निकलता है। शिक्षा से ही राष्ट्र का विकास हो सकता है। प्रत्येक शिक्षक को शिक्षक संघ अपना लगे ऐसा प्रयास होना चाहिए।

पदाधिकारियों का कहना है कि मध्यप्रदेश शिक्षक संघ ने पिछले पचास वर्षों में अनेकों महत्वपूर्ण सोपान तय किए हैं और आज देश के एक शक्तिशाली संगठन के रूप में स्थापित है। उन्होंने संघ की स्थापना से लेकर अब तक 50 वर्षों की उपलब्धियों और रीतिनीति का ब्यौरा देते हुए बताया कि कोरोना संक्रमण के कारण प्रत्यक्ष एकत्रीकरण संभव नहीं हो पाने के कारण आभासी पटल पर कार्यक्रमों का आयोजन बेहतर प्रयास है।

लगातार बढ़ाएंगे शिक्षा की गुणवत्ता

संगठन के प्रदेश महामंत्री क्षत्रवीर सिंह राठौर ने कहा कि कोरोना की दूसरी लहर में स्वर्ण जयंती समारोह के अंतर्गत पूरे वर्ष राज्य में शिक्षा के गुणात्मक विकास पर काम किया जाएगा। उन्होंने कहा है कि संगठन से जुड़ा प्रत्येक पदाधिकारी विद्यालय में बच्चों की शत.प्रतिशत उपस्थिति बढ़ाने बच्चों का सर्वांगीण विकास करने की दिशा में काम करेगा। उन्होंने कहा कि कोरोना का कहर कम सोने के बाद स्थिति सामान्य होते ही व्यापक स्तर पर प्रत्यक्ष बड़े कार्यक्रमों का आयोजन पूरे प्रदेश में किया जाएगा एवं शिक्षा ज्ञान ज्योति यात्रा भी निकाली जाएगी। अक्टूबर 2021 में प्रदेश स्तरीय भव्य समारोह का आयोजन एवं स्मारिका का विमोचन भी किया जाएगा।

वर्चुअल बैठकर कर्मचारी संघ बढ़ा रहा लोक सेवकों का मनोबल

भोपाल। कोरोना संक्रमण से ध्यान रहे सरकारी लोक सेवकों का मनोबल बढ़ाने के लिए राज्य कर्मचारी संघ द्वारा अभिनव पहल की गई है। इस संगठन द्वारा प्रदेश भर में वर्चुअल बैठकों का आयोजन कर कर्मचारियों के धैर्य और साहस में वृद्धि करने की तकनीक बताई जा रही है। संगठन का कहना है कि वर्चुअल बैठक एवं मोबाइल से संपर्क कर कोरोना पीड़ित परिवारों का मनोबल बढ़ाया जा रहा हैं। साथ ही कोरोना टीका और उसकी गाइडलाइन की पालन करने का जन जागरण कर रहे हैं। अनेक पदाधिकारियों एवं परिवारों की कोरोना के कारण मृत्यु होने पर शोक संवेदना भी वर्चुअल बैठक के दौरान शाति प्रार्थना कर रहे हैं। संगठन के प्रदेश महामंत्री हेमंत श्रीवास्तव ने राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में मान्यता प्राप्त कर्मचारी संघों की सूची जमा कराने के निर्देश दिए गए हैं। ऐसे समय में यह सूची जमा करना इसलिए संभव नहीं है क्योंकि पूरे प्रदेश में लॉकडाउन लगा हुआ है। इस कारण सामान्य प्रशासन मंत्री इंदर सिंह परमार को पत्र लिखकर मान्यता प्राप्त संगठनों के पदाधिकारियों की सूची जमा करने की समयावधि बढ़ाने के लिए पत्र लिखा है। इसमें यह मांग भी की गई है कि प्रदेश में शासकीय सेवकों के स्थानांतरण को अभी ना किए जाए। वर्चुअल व्यवस्था के अंतर्गत चंबल संभाग की बैठक आयोजित हुई । जिसमें राष्ट्रीय महामंत्री विष्णु वर्मा, प्रदेश अध्यक्ष विश्वजीत सिंह सिसोदिया, प्रदेश उपाध्यक्ष बादाम सिंह यादव, प्रदेश कोषाध्यक्ष अनिल एडविन, संगठन मंत्री अनिल भार्गव, कार्यालय मंत्री सुरेंद्र सिंह चौहान, प्रदेश मंत्री अशोक शर्मा सहित शिवपुर मुरैना भिंड जिले के अध्यक्ष सचिव कोषाध्यक्ष उपस्थित रहे।

मंत्री को पत्र लिखकर मान्यता प्राप्त संघों की सूची जमा करने की अवधि बढ़ाने की मांग

Gautam

कोरोना से शिक्षकों की मौत का चार सौ तक पहुंचा आंकड़ा, कोरोना योद्धा घोषित करने की मांग

शहर प्रतिनिधि, भोपाल । राजधानी समेत प्रदेश में शिक्षकों की मौत का आंकड़ा चार तक पहुंच गया है। शिक्षक समेत कई कर्मचारी संगठनों ने शिक्षक संवर्ग को कोरोना योद्धा घोषित करने की मांग की है। राज्य कर्मचारी संघ के अध्यक्ष जितेंद्र सिंह का कहना है कि इस त्रासदी में प्रदेश का कर्मचारी जगत पूर्ण लगन एवं निष्ठा से अपनी सेवाएं दे रहा है। करोना फ्रंट लाइन वर्कर के रूप में कई विभागों के कर्मचारियों को कोरोना योद्धा घोषित करते हुए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रासंगिक लाभ दिए जा रहे हैं। वही प्रदेश में एक ऐसा संवर्ग है जो ग्राम स्तर से लेकर शहरी स्तर तक कोरोना के महामारी के निदान में अपनी सेवाएं देता आ रहा है। शिक्षक संवर्ग ऐसा संवर्ग है जिसकी ड्यूटी राज्य के प्रशासनिक अधिकारी जहां उचित होता है वही लगा देते हैं। जैसा की उज्जैन जिले में कलेक्टर ने आदेश किया है कि जिले के प्रत्येक नगर और गांव में सभी शिक्षक सर्दी बुखार और खांसी के मरीजों का सर्वे करेंगे। जब आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आशा कार्यकर्ता यहां तक कि दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी साथी तक को कोरोना योद्धा का दर्जा दिया गया है और फ्रंटलाइन वर्कर माना गया है तो शिक्षक क्यों नहीं। जितेंद्र सिंह का कहना है कि शिक्षकों की कोरोना से मौत हो रही है। शिक्षकों को भी कोरोना योद्धा का दर्जा दिए जाए। वहीं, मप्र शिक्षक कांग्रेस के जिला अध्यक्ष सुभाष सक्सेना का कहना है कि कोरोना ड्यूटी में कार्यरत शिक्षकों को कोरोना योद्धा माना गया है, लेकिन पूरे संवर्ग को कोरोना योद्धा घोषित किया जाना चाहिए। वहीं, मप्र विद्युत कर्मचारी संघ इंटक के महामंत्री बीडी गौतम ने बिजली विभाग के सभी संवर्ग के कर्मचारियों को कोरोना योद्धा घोषित करने की मांग की है।

आउट कर्मचारियों का बीमा कराने की मांग: सेमी गवर्नमेंट एम्पलाइज फेडरेशन ने निगम मंडलों में आउट सोर्स एवं विभिन्न कंपनियों के माध्यम से कार्यरत कर्मचारियों का बीमा कराए जाने की मांग की गई है। संघ के संरक्षक अनिल बाजपेयी का कहना है कि हाल ही में वेयर हाउस कारपोरेशन के फील्ड कर्मचारियों का बीमा कराए जाने का आदेश दिया है। बीमा राशि प्रीमियम का भुगतान संस्थान द्वारा किया जाएगा। इसी प्रकार निगम मंडलों एवं शासन कि कई संस्थाओं में आउट सोर्स विभिन्न कंपनियों के माध्यम से जो कर्मचारी कार्य कर रहे हैं, उनका बीमा कराया जाए। ताकि कोरोना काल जैसी प्राकृतिक विपदा के समय किसी प्रकार की अनहोनी घटना के घटित होने पर आर्थिक राशि प्राप्त हो और परिवार को राहत प्रदान हो सके।

Badri Gautam

शिक्षकों को कोरोना योद्धा घोषित करने की मांग

दतिया, ब्यूरो

मध्यप्रदेश राज्य कर्मचारी संघ जिला शाखा दतिया ने राज्य शासन से शिक्षक संवर्ग को कोरोना योद्धा घोषित कर उन्हें कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना में शामिल करने की मांग की है।

संघ द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति में बताया गया है कि कोरोना महामारी के दौरान शिक्षक क्वारंटाइन निगरानी टीम, कंट्रोल रूम, चैक पोस्ट से लेकर जहां-जहां शासकीय सेवकों की आवश्यकता है वहां शिक्षक अपनी सेवाएं पूरी लगन, मेहनत और ईमानदारी से दे रहे हैं, जबकि सुरक्षा की दृष्टि से पर्याप्त सामग्री, पेयजल उपलब्ध न होने, धूप से बचाव की व्यवस्था न होने के बाद भी शिक्षक निरंतर अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं। इसके बाद भी शिक्षक संवर्ग को अग्रिम पंक्ति कर्मचारी नहीं मान जा रहा है। कोरोना संकट काल में सबसे अधिक संख्या में यदि कोई शासकीय सेवक अपनी सेवाएं दे रहे हैं तो उनमें सबसे अधिक संख्या शिक्षक संवर्ग की है। प्रदेश में सैकड़ों शिक्षकों की इस महामारी से मौत हो चुकी है। इसके बाद भी शिक्षक संवर्ग के साथ भेदभाव किया जा रहा है, जबकि राज्य शासन द्वारा अनुबंधित दैनिक वेतन भोगी से लेकर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, संविदा के आधार पर कार्यरत कर्मचारी, रोजगार सहायक, आउटसोर्स कर्मचारियों तक को कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना में पात्र घोषित किया गया है।

Badri Gautam

जिले में खुलेंगे सात सीएम राइज स्कूल, पहले चरण में प्रदेश में 350

ग्वालियर, न.सं.

प्रदेश सरकार द्वारा बच्चों को अच्छी शिक्षा प्रदान करने के लिए मध्यप्रदेश में 9200 सीएम राइज स्कूल खोले जाएंगे। मध्यप्रदेश में प्रथम चरण में 350 स्कूल खोलने की योजना है। वहीं जिले में सात सीएम राइज स्कूल खुलना है। सीएम राइज स्कूल खुलने पर न पुराने स्कूलों को बंद किया जाएगा और न हीं शिक्षकों को नौकरी से हटाया जाएगा। जानकरी के अनुसार सीएम राइज स्कूल के लिए योग्य व अनुभवी शिक्षकों की नियुक्ति अवश्य की जाएगी।

न स्कूल बंद होंगे और न ही शिक्षक हटेंगे

शिक्षा विभाग द्वारा जिले में सीएम राइज स्कूल खोले जाने के लिए सात विद्यालयों की सूची बनाकर भोपाल भेज दी है। यह विद्यालय निजी स्कूलों की तरह सर्वसुविधायुक्त होंगे। यहां बच्चों के खेलने के लिए पार्क, पार्किंग, लैब एवं डिजीटल कक्षाएं आदि होंगी। अनुभवी शिक्षकों द्वारा बच्चों को शिक्षा प्रदान की जाएगी। जिले में मॉडल स्कूल मुरार, मॉडल स्कूल घाटीगांव, मॉडल स्कूल भितरवार, मॉडल स्कूल डबरा, पद्मा विद्यालय, शिक्षा नगर हायर सेकेण्डरी स्कूल तानसेन नगर एवं शासकीय हायर सेकेण्डरी स्कूल बैरजा ग्रामीण विधानसभा शामिल हैं।

शहरी क्षेत्र में 2000 और ग्रामीण क्षेत्र में 1500 बच्चे पढ़ेंगे

प्राप्त जानकारी के अनुसार शहरी क्षेत्र में जो सीएमराइज स्कूल खोले जाएंगे, उनमें 2000 और ग्रामीण क्षेत्र में 1500 बच्चे पढ़ाई करेंगे। सीएमराइज योजना के अंतर्गत जिन स्कूलों की इमारत जीर्ण-शीर्ण हो गई है, उनका जीर्णोद्धार कराकर सीएम राइज स्कूल बनाया जाएगा। जहां इमारत की व्यवस्था नहीं है, वहां इमारत तैयार की जाएगी।

सीएम राइज योजना के अंतर्गत प्रत्येक स्कूल पर लगभग चार करोड़ रुपए खर्च किए जा सकते हैं। वर्तमान में जितने भी शिक्षक हैं उन्हें उनकी योग्यता के आधार पर इन स्कूलों में शामिल किया जाएगा, हटाया किसी भी शिक्षक को नहीं जाएगा। इस योजना को क्रियान्वयन होने में एक से दो वर्ष का समय लगेगा।

इनका कहना है

"'सीएम राइज स्कूलों की सूची बनाकर शासन को दे दी गई है। इन स्कूलों में बच्चों को सर्वसुविधायुक्त सुविधाएं रहेंगी और अच्छी शिक्षा प्रदान की जाएगी।'"

अशोक दीक्षित, एडीपीसी

Badri Gautam

10वीं-12वीं को छोड़कर शेष कक्षाओं की ऑनलाइन क्लासेस स्थगित

Badri Gautam

रीवा| सभी शासकीय एवं अशासकीय विद्यालयों में कक्षा 10वीं और 12वीं को छोड़कर शेष कक्षाओं की ऑनलाइन क्लासेस 31 मई तक संचालित नही होंगी। आयुक्त लोक शिक्षण ने बताया कि वर्तमान में कोविड संक्रमण विस्तार के कारण विद्यार्थियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा यह निर्णय लिया गया है। यह निर्णय सीबीएसई, आईसीएसई, माध्यमिक शिक्षा मंडल या किसी भी बोर्ड से संबद्ध सभी विद्यालयों पर लागू होगा।

अब 31 मई तक बंद रहेगी ऑनलाइन पढ़ाई

भास्कर न्यूज | सतना

स्कूल शिक्षा विभाग ने ऑनलाइन सत्र के संचालन करने पर रोक लगा दी है। आयुक्त लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि प्री-प्राइमरी, हाईस्कूल तथा हायर सेकंड्री स्कूलों में ऑनलाइन पठन-पाठन का कार्य 31 मई तक नहीं होगा। शासकीय या गैरशासकीय स्कूल यह ऑनलाइन पढ़ाई 31 मई के बाद ही करा सकेंगे। इस आशय के लिए जिला शिक्षा अधिकारी ने समस्त प्राचार्यों एवं मान्यता प्राप्त निजी हाई एवं हायर सेकंड्री स्कूलों को आदेश जारी कर दिए गए हैं। बताया गया कि कोविड-19 के संक्रमण का विस्तार होने के कारण विद्यार्थियों में भय एवं तनाव की स्थिति निर्मित हो रही है। इस कारण ऑनलाइन पढ़ाई पर निर्धारित समय तक के लिए रोक लगाई गई है।

बताया गया कि 10वीं और 12वीं को छोड़कर शेष सभी कक्षाओं में ऑनलाइन पढ़ाई का संचालन नहीं होगा।

दूरदर्शन और रेडियो पर होता था प्रसारण

उल्लेखनीय है कि कोरोना संक्रमण के चलते लम्बे समय से बंद चल रहीं स्कूलों के कारण छात्र-छात्राओं को पठन-पाठन से जोड़े रखने के लिए अपना घर अपना विद्यालय योजना सहित वाट्सएप के माध्यम से पठनीय सामग्री छात्रों को भेजी जाती थी। दूरदर्शन और रेडियो के माध्यम से भी कक्षाओं का प्रसारण किया जाता था, लेकिन अब एक माह तक यह सभी गतिविधियां बंद रहेंगी।

Badri Gautam

यूजीसीः सभी परीक्षाओं और प्रवेश प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की तैयारी

नई दिल्ली, जेएनएन। देश में कोरोना की दूसरी लहर को देखते हुए विश्वविद्यालयों और कॉलेजों की आगामी सभी प्रस्तावित परीक्षाओं और प्रवेश प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की तैयारी हो रही है। जल्द ही इसके लिए यूजीसी गाइडलाइन जारी करेगा। इसके साथ पाठ्यक्रम में भी कटौती की जा सकती है। उच्च शिक्षण संस्थानों ने अपने ज्यादा से ज्यादा कोर्सों को ऑनलाइन या फिर दूरस्थ शिक्षा के माध्यमों से संचालित करने ■ शेष पृष्ठ 9 पर

Badri Gautam

नए शैक्षिणक सत्र से होगा लागू

सीबीएसई ने कक्षा 9,10,11 व 12वीं में परीक्षा का पैटर्न बदला

हरिभूमि न्यूज ▶▶| नई दिल्ली

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) ने क्लास 9, 10, 11 या 12 इन चारों कक्षाओं के लिए होने वाली परीक्षाओं के पैटर्न में बदलाव किया है। सीबीएसई का नया एग्जाम पैटर्न शैक्षणिक सत्र 2021-22 से लागू होगा। क एकेडेमिक सेशन 2021-22 के लिए सीबीएसई बोर्ड ने नया असेसमेंट और ईवैल्यूएशन पैटर्न तैयार किया है। बोर्ड के ट्रेनिंग एंड स्किल डेवलपमेंट विभाग के निदेशक विश्वजीत साहा ने बताया कि 'नई मूल्यांकन प्रक्रिया कंपीटेंसी बेस्ड एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए बनाई गई है।

Badri Gautam

कक्षा 9-10 के लिए ऐसा पैटर्न

क्लास 9 और 10 की परीक्षा में कंपीटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस की संख्या 20 से बढ़ाकर 30 कर दिये गये हैं। इसमें मल्टीपल च्वाइस, केस आधारित और कोर्स आधारित इंटीग्रेडेट क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। वहीं, प्रश्नपत्र के 20% सवाल ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे

कक्षा 11-12 के लिए ये बदलाव

क्लास 11 और 12 की बात करें, तो पिछली बार की तरह कंपीटेंसी बेस्ड सवाल 20% होंगे। जबकि ऑब्जेक्टिव टाइप सवालों की संख्या 10% से बढ़ाकर 20% कर दी गई है। वहीं, शॉर्ट और लॉन्ग आंसर टाइप सवाल 70% से घटाकर 60% कर दिए गए हैं।

CBSE ने 9वीं से 12वीं तक एग्जाम पैटर्न बदला

रिपोर्टर • IamBhopal
Mobile no. 9827080406

सीबीएसई ने 9वीं से 12वीं की परीक्षाओं के पैटर्न में बदलाव किया है। यह बदलाव नई शिक्षा नीति के तहत किया गया है। बोर्ड के ट्रेनिंग एंड स्किल डेवलपमेंट विभाग के निदेशक विश्वजीत साहा ने बताया कि नई मूल्यांकन प्रक्रिया कंपीटेंसी बेस्ड एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए बनाई गई है। इसमें परीक्षा के ओवरऑल मार्क्स और समय में कोई बदलाव नहीं है। क्वेश्चन पैटर्न बदला गया है। ऐसा इसलिए किया गया है, क्योंकि छात्रों के पढ़ने और टीचर्स के पढ़ाने के का तारीका बदला है।

Badri Gautam

क्लास 9-10 : कंपीटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस की संख्या 20 से बढ़ाकर 30 कर दी गई है। मल्टीपल च्वाइस, केस आधारित और कोर्स आधारित इंटीग्रेडेट सवाल पूछे जाएंगे। 20% सवाल ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे (पहले की तरह)। जबकि शॉर्ट और लॉन्ग आंसर टाइप सवालों की संख्या घटकर 50% रह जाएगी।

क्लास 11-12 : पिछली बार की तरह कंपीटेंसी बेस्ड सवाल 20% होंगे, जबकि ऑब्जेक्टिव टाइप सवालों की संख्या 10% से बढ़ाकर 20% कर दी गई है। वहीं, शॉर्ट और लॉन्ग आंसर टाइप सवाल 70% से घटाकर 60% कर दिए गए हैं।

ओपन बुक सिस्टम से कराएं बोर्ड एग्जाम : एनएसयूआई

भोपाल। एनएसयूआई ने माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा आयोजित होने वाली दसवीं बारहवीं की परीक्षाएं ओपन बुक सिस्टम से आयोजित कराने की मांग स्कूल शिक्षा विभाग से की है। इसको लेकर एनएसयूआई ने स्कूल शिक्षा मंत्री को पत्र लिखा है। एनएसयूआई का कहना है कि प्रदेश में तेजी से कोरोना संक्रमण फैल रहा है, ऐसी स्थिति में ऑफलाइन एग्जाम कराना विद्यार्थियों स्वास्थ्य के लिए घातक साबित हो सकता है।

Badri Gautam

जवाहर नवोदय विद्यालय कक्षा 6 वीं की परीक्षा स्थगित

सतना। जवाहर नवोदय विद्यालय रीकेवारा के प्राचार्य अमरीश चौहान ने बताया कि शैक्षणिक सत्र 2021-22 के लिए जवाहर नवोदय विद्यालय कक्षा 6वीं में प्रवेश के लिये जिले के केन्द्रों में 16 मई 2021 को होने वाली परीक्षा को वर्तमान स्थिति के मद्देनजर स्थगित कर दिया गया है। पुनर्निधारित तिथि, चयन परीक्षा की तिथि से कम से कम 15 दिन पूर्व अधिसूचित की जाएगी।

Badri Gautam

आनलाइन कक्षाओं पर रोक, फीस पर फैसला नहीं

जबलपुर (नईदुनिया प्रतिनिधि)। आनलाइन कक्षाओं को कोरोना संक्रमण की वजह से बंद करने का फरमान तो जारी हो गया, लेकिन फीस के मुद्दे पर शासन की चुप्पी बनी हुई है। इधर, निजी स्कूल किसी भी तरह विद्यार्थियों से शिक्षण शुल्क वसूलने का प्रयास कर रहे हैं। आनलाइन कक्षाओं के दौरान ही विद्यार्थियों को फीस जमा करवाने की हिदायत दी जा रही है। वहीं लाकडाउन की वजह से अभिभावक समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर कैसे फीस जमा की जाए। स्कूल नए शैक्षणिक सत्र में पूरी फीस मांग रहे हैं।

शैक्षणिक सत्र 2020-21 के लिए स्कूल शिक्षा विभाग ने सिर्फ निजी स्कूलों से ट्यूशन फीस लेने के निर्देश दिए थे। वो भी विना किसी दवाव के लिए जाना था। इसके लिए स्कूलों को किश्त में राशि ली जानी थी। यदि किसी अभिभावक द्वारा फीस नहीं जमा की गई है उसके वावजूद विद्यार्थी को कक्षा और परीक्षा ना ही नतीजे रोकने की अनुमति स्कूल प्रवंधन को थी। अव नया सत्र प्रारंभ हो चुका है। आनलाइन कक्षाएं भी लग रही है। ऐसे में स्कूलों ने पहले ही अभिभावकों को पूरी फीस जमा करने के लिए संदेश जारी करना शुरू कर दिया है। स्कूल प्रवंधन ने कहा है कि फीस पूरी भरें यदि किसी तरह की वाद में सरकारी आदेश जारी होते हैं तो अतिरिक्त भुगतान की गई राशि का समायोजन किया जाएगा। इधर स्कूल खुलने से पहले दोवारा लाकडाउन लग चुका है। संक्रमण की भयावहता को देखकर अभिभावक फिलहाल अगले कई माह तक स्कूलों में विद्यार्थियों को भेजने की स्थिति में नहीं है। ऐसे में वंद कक्षाओं के लिए फीस वसूलना अभिभावकों की दृष्टि से जायज नहीं माना जा रहा है।

एक मई से आनलाइन कक्षाओं पर पावंदी

कोरोना के वढ़ते संक्रमण को देखते हुए प्रदेश सरकार ने 10वीं और 12वीं की वोर्ड परीक्षाओं को छोड़कर अन्य सभी आनलाइन कक्षाओं पर एक मई से रोक लगा दी है। ये पावंदी एक माह तक लागू रहेगी। अव कक्षा 1 से लेकर 9वीं और 11वीं के विद्यार्थी 31 मई तक आनलाइन क्लास में नहीं पढ़ पाएंगे। इस संवंध में लोक शिक्षण संचालनालय ने मंगलवार को आदेश जारी कर दिया है। आदेश में कहा गया है कि वर्तमान में कोविड-19 संक्रमण लगातार फैलने के कारण विद्यार्थियों में भय व तनाव की स्थिति निर्मित हो रही है। इस कारण 10वीं और 12वीं वोर्ड को छोड़कर अन्य कक्षाओं की आनलाइन कक्षाएं एक मई से 31 मई 2021 तक के लिए निरस्त की जा रही हैं। ये आदेश मप्र वोर्ड के अलावा केंद्रीय वोर्ड और आइसीएससी वोर्ड के स्कूलों पर भी लागू होगा।

Badri Gautam

मई में होने वाली चार्टर्ड अकाउंटेंट परीक्षाएं स्थगित

भोपाल। मई 2021 में होने जा रही चार्टर्ड अकाउंटेंट इंटर और फाइनल की परीक्षाएं स्थगित कर दी गई हैं। आइसीएआइ ने इस संबंध में नोटिस जारी कर दिया है। कोविड-19 के कारण इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने नोटिस जारी कर परीक्षाएं स्थगित करने की सूचना दी है। आईसीएआई ने नोटिस में लिखा है कि कोविड-19 महामारी के मौजूदा हालात के मद्देनजर हमने एग्जाम स्थगित करने का फैसला किया है। पहले सीए फाइनल एग्जाम का आयोजन 21 और सीए इंटरमीडिएट एग्जाम 22 मई 2021 को होने वाला था। -(**नरि**)

Badri Gautam

बौद्ध-भारतीय ज्ञान अध्ययन विवि से पीएचडी की विदेशों में बढ़ी डिमांड

सांची विवि में प्रवेश परीक्षा के लिए आए 80 आवेदन, 12 फीसदी विदेशी विद्यार्थी

विश्वविद्यालय की ओर से अंतिम तारीख में हुई बढ़ोतरी इससे विद्यार्थियों की संख्या में इजाफा होने की संभावना है

हरिभूमि न्यूज ▶▶| भोपाल

सांची बौद्ध-भारतीय ज्ञान अध्ययन विश्वविद्यालय से पीएचडी के लिए अब विदेशी विद्यार्थी भी खूब रुचि दिखा हैं। प्रवेश परीक्षा के लिए अब तक विवि में करीब 80 आवेदन आए हैं, जिसमें से 12 फीसदी आवेदन दूसरे देशों के विद्यार्थियों ने किए हैं। इन आवेदनों में पांच श्रीलंका, दो म्यानमार और एक स्वीडन, एक वियतनाम और न्यूजीलैंड से जमा किए गए है। वहीं दूसरी ओर विवि पीएचडी के लिए प्रवेश परीक्षा के फार्म जमा करने की अंतिम तारीख में भी एक फिर बढ़ोतरी की है, जिससे विदेशी विद्यार्थियों की संख्या में इजाफा होने की संभावना है। कुलपति नीरजा ए गुप्ता ने बताया कि रेगुलर के साथ पार्ट टाइम पीएचडी की व्यवस्था की गई है। इससे काफी शोधार्थियों को राहत मिलेगी। विवि ने एससी-एसटी और दिव्यांग विद्यार्थियों की परीक्षा फीस 1200। उनके अलावा सभी वर्ग की 1500 फीस निर्धारित की है। विवि ने विदेशी विद्यार्थियों की फीस में 66 फीसदी इजाफा किया है। एनआरआई विद्यार्थियों को प्रवेश परीक्षा में शामिल होने 2250 फीस का भुगतान करना होगा।

◆ कुलपति नीरजा ए गुप्ता ने बताया कि रेगुलर के साथ पार्ट टाइम पीएचडी की भी है व्यवस्था

अब तीस अप्रैल तक कर सकेंगे आवेदन

विवि ने प्रवेश परीक्षा के फार्म जमा करने की अंतिम तारीख में एक बार फिर बढ़ोतरी करते हुए तीस अप्रैल कर दिया है। यानि अब विद्यार्थी तीस अप्रैल तक आवेदन कर पाएंगे। पूर्व में अंतिम तिथि 26 अप्रैल तय की गई थी और 28 अप्रैल को योग्य उम्मीदवारों की सूची जारी होनी थी। हालांकि तारीख बढ़ने बाद अब विवि तीन मई को उम्मीदवारों की सूची जारी की जाएगी।

चीनी भाषा में पीएचडी करने की चार सीटें

जानकारी के मुताबिक विवि बौद्ध अध्ययन, वैदिक अध्ययन, भारतीय शिक्षा एवं समग्र विकासए योग, भारतीय चित्रकला, हिन्दी, अंग्रेजी और चीनी भाषा में पीएचडी करा रहा है। ये विषय देश-विदेश के चुनिंदा विवि में संचालित हो रहे हैं। यहां तक उनके पास पीएचडी कराने की व्यवस्था नहीं हैं। लगातार विद्यार्थियों के डिमांड को देखते हुए कुलपति ने आवेदन करने की स्वीकृति दे दी है। विद्यार्थी प्रवेश परीक्षा में शामिल हो सकेंगे। चीनी भाषा में पीएचडी करने चार सीटें रखी गई हैं।

Badri Gautam

नई व्यवस्था... उच्च शिक्षा विभाग ने लिया फैसला

निजी कॉलेजों में फैकल्टी रखने के लिए बनेगा सिलेक्शन सिस्टम

इंदौर/ भोपाल | DBStar

प्रदेश के उच्च शिक्षा से जुड़े प्राइवेट कॉलेजों में फैकल्टी रखने के लिए केंद्रीयकृत चयन प्रणाली बनेगी। प्राइवेट कॉलेजों में पदस्थ शिक्षकों के बार-बार संस्थान बदलने की वजह से शिक्षा की गुणवत्ता प्रभावित होती है। इसी के साथ कई बार प्राइवेट कॉलेज भी उनके यहां पदस्थ फैकल्टी के संबंध में सही जानकारी नहीं देते हैं। प्राइवेट कालेजों में हर साल छात्रों के दाखिला लेने के दौरान कई बार फैकल्टी बीच में ही संस्थान बदल बदल लेती है। हाल में स्थायी समिति की बैठक में भी यह मुद्दा उठा था। इसके बाद उच्च शिक्षा विभाग ने इस दिशा में तैयारी शुरू कर दी है। अधिकारियों के मुताबिक ऐसे मामले भी सामने आए हैं जब शिक्षकों का स्थायी रूप से चयन और नियमित रूप से काम करने की स्थिति नहीं मिलती है। इस वजह से बड़ी संख्या में शिक्षक नौकरी छोड़ देते हैं या दो-तीन साल में कार्यस्थल बदल लेते हैं।

तीन कैटेगरी : काम का ऐसे हुआ बंटवारा

1- पीएचडी :	2- केवल नेट/	3- पीजी
शिक्षण, अनुसंधान निदेशक व मूल्यांकन आदि का काम कर सकते हैं।	सेट : शिक्षण व मूल्यांकन का काम कर सकते हैं।	55% अंक के साथ : केवल शिक्षण कार्य करेंगे।

यूजीसी में हर साल होगा पंजीयन और अपडेशन

पहली और दूसरी श्रेणी के शिक्षकों की अनुपलब्धता होने पर ही तीसरी श्रेणी के शिक्षकों से शिक्षण कार्य करवाया जाएगा। इसके लिए शिक्षकों का रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। इसमें यूजीसी द्वारा निर्धारित योग्यता प्राप्त अभ्यर्थी अपना पंजीयन करवा सकेंगे। यह पंजीयन हर साल अपडेट किया जाएगा। जो अभ्यर्थी एक बार इसमें पंजीयन करवाएगा उसे यूनिक आईडी मिलेगा। इस यूनिक आईडी से पंजीकृत सिस्टम से कालेज भी इन्हें रख सकते हैं। गौरतलब है कि शिक्षकों के संबंध में कोड 28 का कई कॉलेज पालन नहीं करते हैं। नए सिस्टम इसे इनकी मॉनीटरिंग हो सकेगी। इस सिस्टम में निर्धारित वेतनमान शिक्षकों को देना होगा। निजी कॉलेजों में फैकल्टी को रखने के लिए पूर्णकालिक, अंशकालिक, किसी एक विषय को पढ़ाने की तय समय अवधिक के लिए योग्य शिक्षकों का राज्य स्तरीय पैनल तैयार होगा।

Badri Gautam

जेईई एडवांस्ड की तारीख बदलेगी

सिटी रिपोर्टर। आईआईटी में एडमिशन के लिए होने वाले जेईई एडवांस्ड 2021 का आयोजन इस साल 3 जुलाई को होना है। लेकिन, इस तारीख में अब बदलाव हो सकता है। आईआईटी खड़गपुर ने बताया है कि मौजूदा परिस्थितियों में परीक्षा को लेकर हजारों स्टूडेंट्स के फोन कॉल्स और ई-मेल्स आ रहे हैं। आईआईटी जेईई एडवांस्ड के चेयरमैन देबाशीष चक्रवर्ती ने कहा, जिस तरह के हालात हैं, हम जेईई एडवांस्ड 2021 की तारीख बदल सकते हैं। जरूरी है कि जेईई मेन्स की परीक्षा के बाद जेईई एडवांस्ड की तैयारी के लिए स्टूडेंट्स को वक्त दिया जाए।

Badri Gautam

आईआईएम इंटीग्रेटेड प्रोग्राम के आवेदन शुरू

सिटी रिपोर्टर। अब आप 12वीं के बाद सीधे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट (आईआईएम) में एडमिशन पा सकते हैं। इसके लिए अलग-अलग आईआईएम द्वारा अलग-अलग प्रवेश परीक्षाएं कराई जाती हैं। आईआईएम इंदौर में 12वीं के बाद एडमिशन के लिए आईपीमैट एग्जाम लिया जाता है। आईपीमैट इस बार 16 जुलाई 2021 को होगी। इसके लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस शुरू हो गई है। जम्मु आईआईएम में भी इंट्रीग्रेटेड मैनेजमेंट प्रोग्राम में एडमिशन मिल सकता है। इसके लिए आवेदन की आखिरी तारीख 30 अप्रैल रखी गई है। परीक्षा 20 जुलाई को होगी।

CMA: अब 20 मई तक जमा होंगे फॉर्म

भोपाल। इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (सीएमए) ने जून में होने वाली अपनी फाउंडेशन कोर्स, इंटरमीडिएट और फाइनल परीक्षाएं जुलाई तक के लिए स्थगित कर दी हैं। सीएमए ने जून में होने वाली अपनी फाउंडेशन कोर्स, इंटरमीडिएट और फाइनल परीक्षाएं जुलाई तक के लिए स्थगित कर दी गई हैं। इसके साथ ही परीक्षा का फॉर्म भरने की अंतिम तिथि भी 20 मई तक बढ़ा दी गई है। हालांकि, अभी यह तय नहीं हुआ परीक्षाएं ऑनलाइन होंगी या ऑफलाइन। वहीं, आइसीएमएआइ ने फाउंडेशन कोर्स परीक्षा का टाइमटेबल जारी कर दिया है। परीक्षा 23 जुलाई को दो शिफ्ट में होगी।

Badri Gautam

ड्यूटी में लापवाही पर 4 सहा प्राध्यापकों को नोटिस जारी

पीपुल्स संवाददाता ● दमोह

मो.नं. 8435502322

विधानसभा उपनिर्वाचन 2021 हेतु विधानसभा क्षेत्र 55 दमोह की मतगणना प्रशिक्षण में अनुपस्थित रहने पर सरकारी कॉलेज जबेरा के सहायक प्राध्यापक अमितेष सोनी एवं सरकारी कॉलेज हटा के सहायक प्राध्यापक प्रशांत सूर्यवंशी, मनोज सिंह गुर्जर और राहुल चौधरी को उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने कारण बताओ नोटिस जारी किया है। इन्हें 27 अप्रैल को प्रशिक्षण प्राप्त करने आदेशित किया गया था, लेकिन ये अनुपस्थित रहे।

नोटिस में लिखा गया गई कि यह कृत्य मप्र सिविल सेवा आचरण नियम 1965 एवं लोक प्रतिनिधित्व नियम 1950 का स्पष्ट उल्लंघन होकर अपने कर्तव्य के प्रति घोर लापरवाही एवं स्वेच्छाचारिता को प्रकट करता है जो गंभीर कदाचरण की श्रेणी में आता है, क्यों न मप्र सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील)-1966 के तहत दंडित किए जाने के लिए कार्रवाई की जाए। इस संबंध में इनसे 24 घंटे के भीतर जवाब प्रस्तुत करने को भी कहा गया है। ज्ञातव्य हो कि चुनाव संबंधी कार्य आवश्यक और अनिवार्य सेवा के अंतर्गत आते हैं, जिसमें लापरवाही को अत्यंत गंभीरता से लिया जाता है। पूर्व में यहां के प्रभारी प्राचार्य सूरज प्रसाद पचौरी की कार्यपद्धति पर भी प्रश्न चिन्ह लगे हैं।

वहीं हटा के प्रभारी प्राचार्य पीके ढाका को एक सहायक प्राध्यापक के अस्वस्थ होने की जानकारी तो है। लेकिन अन्य दो के अनुपस्थित होने का स्पष्ट जबाव नहीं है।

Badri Gautam

दिसंबर माह से छात्र-छात्राओं को नहीं मिला सूखा राशन, आवंटन पर रोक

स्कूलों में 2 लाख 10 हजार बच्चों के एमडीएम की सुध भूली सरकार

पीपुल्स संवाददाता ● टीकमगढ़
मो.नं. 9691939149

कोरोना संक्रमणकाल में स्कूली छात्र-छात्राओं को मिलने वाले सूखा राशन की व्यवस्था एक बार फिर गड़बड़ा गई है। जिले में पिछले दिसंबर माह से बच्चों को राशन नहीं मिला है। अधिकारिक सूत्रों के अनुसार शासन स्तर से ही आवंटन पर रोक लगा दी गई हैं। विदित है कि कोरोना संक्रमण के चलते शासकीय स्कूल बंद है। इसमें कोई भी बच्चा मध्याह्न भोजन से वंचित न रहे, इसके लिए बच्चों को खाद्य सामग्री उपलब्ध कराई जानी थी। किंतु बच्चों के प्रति सरकार व प्रशासन सुध नहीं ले रहा है।

जिले में एक हजार से अधिक समूहों द्वारा आंगनबाड़ियों के साथ प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों में मध्याह्न भोजन वितरण किया जा रहा था। कोरोना वायरस से स्कूल बंद कर चल रहे हैं। शासन ने समूह संचालकों को मध्याह्न भोजन की जगह सूखा राशन वितरण करने के निर्देश दिए थे। लेकिन जिले में दिसम्बर माह से प्राथमिक एवं माध्यमिक स्कूल के करीब 2 लाख 10 हजार छात्र-छात्राओं को सूखा राशन नहीं मिल रहा है। कोरोना

फाईल फोटो।

काल में प्रदेश सरकार ने स्कूल बंद होने पर अप्रैल से जुलाई तक बच्चों के खाते में खाना पकाने की राशि को दिया जा रहा था। इसमें प्राथमिक स्कूल के हर बच्चे प्रतिदिन के हिसाब से 4.97 रुपए और माध्यमिक स्कूल के हर बच्चे को 7.45 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से दिया जाना बताया। इसके बाद राज्य शासन ने खाद्य सुरक्षा योजना के तहत स्कूल के बच्चों को सूखा राशन देने का निर्णय लिया। जुलाई माह से लगातार स्कूली बच्चों को सूखा राशन दिया जा रहा था, लेकिन पिछले पांच माह से राशन देना पूरी तरह बंद कर दिया गया है। विभागीय अधिकारियों का कहना है कि शासन स्तर से ही आवंटन रुका हुआ है। वहीं राशन मुहैया होने को लेकर कोई संतोषप्रद जवाब नहीं मिल रहा है।

Badri Gautam

नवंबर तक मिला राशन

विभागीय जानकारी अनुसार प्राथमिक एवं प्राथमिक स्कूल के बच्चों को सूखा राशन दिया जा रहा था। इसमें प्राथमिक स्कूल के हर बच्चे को स्वयं सहायता समूह के माध्यम से 100 ग्राम एवं प्राथमिक स्कूल के हर बच्चे को 150 ग्राम हर दिन के हिसाब से देने का निर्णय लिया गया। इसके बाद जुलाई से नवंबर तक प्राथमिक एवं माध्यमिक स्कूल के बच्चों को सूखा राशन दिया गया। इसमें प्राथमिक स्कूल के हर बच्चे को हर दिन के हिसाब से 100 ग्राम सूखा राशन तथा तीन माह का दो किलो दाल एवं 525 ग्राम तेल दिया गया। मिडिल स्कूल के हर बच्चे 150 ग्राम प्रतिदिन सूखा राशन एवं तीन माह का तीन किलो दाल एवं 738 ग्राम तेल दिया गया। किन्तु शासन अब बच्चों को एमडीएम मुहैया नहीं करा पा रही है। निवाड़ी और टीकमगढ़ में प्राथमिक और माध्यमिक स्कूल 2311 है। स्कूलों में 2 लाख 10 हजार के करीब बच्चें दर्ज है।

जिपं से मिलेगी जानकारी

इसकी जानकारी जिला पंचायत से मिलेगी।

– हनुमंत सिंह चौहान,
डीपीसी, टीकमगढ़

कॉलेजों की फीस तय नहीं फिर होगी मनमानी वसूली

उच्च शिक्षा विभाग ने 2019 में विवि को दी जिम्मेदारी

पीपुल्स संवाददाता ● भोपाल
मो.नं. 9893231237

उच्च शिक्षा विभाग द्वारा कॉलेजों में प्रवेश प्रक्रिया जून-जुलाई में होगी। लेकिन फीस को लेकर असंमजस है। ऐसे में नए विद्यार्थियों को कॉलेज डिसाइड करने में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।

शासन ने कॉलेजों की फीस तय करने की जिम्मेदारी संबंधित क्षेत्र के विश्वविद्यालयों को दी है। विश्वविद्यालयों ने 28 दिसंबर 2019 को बैठक में सेंट्रल कमेटी गठित कर कॉलेजों की फीस तय करने का निर्णय लिया था। कमेटी का गठन विवि को करना था। लेकिन अभी स्थिति यह है कि आधी-अधूरी कमेटी बनी है।

विवि और संबद्ध कॉलेज

बरकतउल्ला विश्वविद्यालय भोपाल	386
जीवाजी विश्वविद्यालय ग्वालियर	250
देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर	167
रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर	178
अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय रीवा	127
विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन	101

प्रवेश प्रक्रिया में दो माह शेष अभी प्रपोजल तक तैयार नहीं

प्रवेश प्रक्रिया शुरू होने में दो माह बचे हैं। नियम बनाने के बाद निजी कॉलेज फीस निर्धारण के संबंध में संबंधित विवि को प्रपोजल देंगे। यह प्रपोजल विभिन्न पाठ्यक्रमों के आधार पर अलग-अलग होगा। इसके बाद विवि फीस तय करेगा। कोरोना संक्रमण के कारण यह मामला अटका हुआ है।

कॉलेजों में सुविधा के हिसाब से तय करनी थी फीस

विश्वविद्यालयों को संबद्ध कॉलेजों की सुविधाओं और छात्र संख्या के हिसाब से फीस तय करनी थी। उच्च शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने बताया कि जल्द ही वर्चुअल बैठक होनी है। इसमें फीस निर्धारण को लेकर चर्चा की जाएगी। पारंपरिक विश्वविद्यालयों से संबद्ध निजी कॉलेजों में चलने वाले बीए, बीकॉम, बीएससी, एमए, एमएससी, एमकॉम आदि की फीस तय करने का अधिकार अब तक सरकारी नोडल कॉलेजों को था, इस साल से शासन ने यह अधिकार भी विवि को दे दिया है।

कुलपति की अध्यक्षता में बनाई है कमेटी, जल्द होगी बैठक

कुलपति की अध्यक्षता में कमेटी बना दी गई है। इसमें सरकारी और प्राइवेट कॉलेजों के तीन-तीन प्राचार्यों को मेंबर बनाया गया है। शीघ्र ही कमेटी की बैठक कर आगे की कार्रवाई की जाएगी। -डॉ. एच.एस. त्रिपाठी, रजिस्ट्रार, बीयू २

Badri Gautam

बड़वानी जिले के अजराड़ा गांव में प्रशासन की कार्रवाई

शादी में पहुंचे 300 लोग, शिक्षक व सचिव को हटाया, सरपंच को पद से अलग किया

पीपुल्स ब्यूरो ● बड़वानी
मो.नं. 9425088883

जिला कलेक्टर शिवराज सिंह वर्मा ने ग्राम अजराड़ा में एक वैवाहिक समारोह में निर्धारित संख्या का उल्लंघन कर 300 लोगों के शामिल होने पर प्राथमिक शिक्षक और ग्राम पंचायत सचिव को निलंबित कर दिया। इसके अलावा सरपंच को पद से पृथक करने के निर्देश दिए हैं।

कलेक्टर वर्मा ने 26 अप्रैल को यहां ग्राम अंजराणा में एक वैवाहिक समारोह में 300 लोगों के भाग लेने पर आयोजनकर्ता प्राथमिक शिक्षक गुमान सिंह को निलंबित कर दिया है। वहीं कर्तव्य निर्वहन नहीं करने पर ग्राम पंचायत सचिव संतोष धनगर को भी निलंबित कर दिया है। साथ ही जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी ऋतुराज सिंह को ग्राम पंचायत के रोजगार सहायक सुखलाल गुसाई एवं सरपंच वाहरिया को पद से अलग कर वैधानिक कार्यवाही के निर्देश भी दिए हैं।

अभाली गांव सील नहीं किया, सचिव, सरपंच पर कार्रवाई

कलेक्टर ने जिले के ग्राम अभाली में कोरोना पॉजीटिव मामले पाए जाने के बाद भी ग्राम को सील नही करने पर संबंधित ग्राम पंचायत के सचिव और सरपंच को पद से अलग करने की कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। गौरतलब है कि बड़वानी जिले में फिलहाल 847 कोरोना संक्रमित लोगों का इलाज चल रहा है। अभी तक बड़वानी जिले में 6,673 लोग पॉजीटिव पाए गए, जिसमें से 5,589 लोगों को इलाज के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया है। जिले में अब तक 48 लोगों की मौत हुई है।

आलीराजपुर जिले का मामला

विवाह में डीजे पर नाच रहे दूल्हा दुल्हन सहित सात पर कार्रवाई

जिले में कोरोना के संबंध में जारी प्रतिबंधात्मक आदेश का उल्लंघन करने पर दुल्हा-दुल्हन और ग्राम सरपंच सहित सात लोगों पर प्रकरण दर्ज किया गया है। कोरोना संक्रमण के मद्देनजर आलीराजपुर जिले में प्रतिबंधात्मक आदेश के बावजूद जिले के चन्द्रशेखर आजाद नगर जनपद क्षेत्र के ग्राम छोटा खुटाजा में आयोजित एक विवाह कार्यक्रम में डीजे के साथ करीब 150 से 200 लोगों को एकत्र होने और कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन करने के मामले में सात लोगों पर प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। इस कार्रवाई में दला अजनार, रूपली अजनार निवासी छोटा खुटाजा, विकेश बामनिया निवासी संदा, चेनिया बामनिया निवासी संदा, डीजे मालिक रमेश निवासी ग्राम छोटा खुटाजा, ग्राम पंचायत छोटा खुटाजा सरपंच मदन मावी और चौकीदार सुरेश मावी पर भादवि की धाराओं, आपदा प्रबंधन अधिनियम की धाराओं और म.प्र कोलाहल नियंत्रण अधिनियम की धाराओं के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है।

यह है मामला

उल्लेखनीय है कि ग्राम छोटा खुटाजा में दुल्हा-दुल्हन करीब 150 से 200 बारातियों के साथ विवाह कार्यक्रम में डीजे पर नाच रहे थे। इस विवाह कार्यक्रम के संबंध में ग्राम सरपंच और चौकीदार द्वारा प्रशासन को जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई। जिस पर संबंधितों पर प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है।

Badri Gautam

राष्ट्रीय आदिवासी छात्र शिक्षा समिति (NESTS)

(जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार, के अंतर्गत एक स्वायत्त संगठन)

भू-तल, गेट नं -३ ए, जीवन तारा बिल्डिंग, संसद ,मार्ग, नई दिल्ली -110001

एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय शिक्षण कर्मचारी चयन परीक्षा (ETSSE) – 2021

राष्ट्रीय आदिवासी छात्र शिक्षा समिति (NESTS), जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार के अंतर्गत एक स्वायत्त संगठन, एकलव्य मॉडल आवासीय स्कूल (EMRS) मध्य प्रदेश के लिए शिक्षण स्टाफ जैसे प्रधानाचार्य, उप- प्रधानाचार्य, पीजीटी और टीजीटी की भर्ती के लिए 31-03-2021 को प्रकाशित विज्ञापन के तहत ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित कर रहा है!

ETSSE 2021 के लिए ऑनलाइन आवेदन, शैक्षिक योग्यता, शिक्षण अनुभव (जहां भी लागू हो) और अन्य पात्रता मानदंड आदि के संबंध में विस्तृत सूचना Information Bulletin (विवरणिका) में https://recruitment.nta.nic.in वेबसाइट पर उपलब्ध है।पात्र तथा **राज्य के अधिवासित** इच्छुक उम्मीदवार रिक्त पदों के लिए दिनांक (विस्तारित तारीख) 31.05.2021 (23:50 बजे) तक परीक्षा शुल्क-सह-ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं| पदवार रिक्तियों की स्थिति नीचे दी गई है:

SL. No.	Name of the Post with Subject		Vacant Positions	Category - Wise Vacant Positions					ओपन रिक्तियां					रिक्तियों में से मध्यप्रदेश की मूल निवासी महिला अभ्यर्थियों हेतु आरक्षित पदों की संख्या					मध्यप्रदेश के मूल निवासी दिव्यांगजन हेतु आरक्षित पदों की संख्या ¼6 प्रतिशत½				भूतपूर्व सैनिकों हेतु आरक्षित पदों की संख्या ¼10 प्रतिशत½ केवल पुरूष				
				UR	SC	ST	OBC	EWS	UR	SC	ST	OBC	EWS	UR	SC	ST	OBC	EWS	VH	HH	OH	MD	UR	SC	ST	OBC	EWS
1	Principal		32	9	5	6	9	3	6	3	4	6	2	3	2	2	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Vice Principal		32	9	5	6	9	3	6	3	4	6	2	3	2	2	3	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
3	Post Graduate Teacher																										
	I	ENGLISH	58	17	9	11	16	5	9	5	6	8	2	8	4	5	8	3	1	0	1	0	0	0	0	0	0
	II	HINDI	51	14	8	11	13	5	7	4	6	6	3	7	4	5	7	2	1	0	1	0	0	0	0	0	0
	III	PHYSICS	56	16	9	12	14	5	8	5	6	7	2	8	4	6	7	3	1	0	1	0	0	0	0	0	0
	IV	CHEMISTRY	58	16	9	12	16	5	8	4	6	8	2	8	5	6	8	3	1	1	1	0	0	0	0	0	0
	V	MATHS	56	16	8	12	15	5	8	4	6	8	2	8	4	6	7	3	1	0	1	0	0	0	0	0	0
	VI	ECONOMICS	59	17	9	12	16	5	8	4	6	8	3	9	5	6	8	2	1	1	1	1	0	0	0	0	0
	VII	BIOLOGY	55	15	9	12	14	5	7	5	6	7	2	8	4	6	7	3	1	0	1	0	0	0	0	0	0
	VIII	HISTORY	59	17	9	12	16	5	9	4	6	8	3	8	5	6	8	2	1	1	1	1	0	0	0	0	0
	IX	GEOGRAPHY	59	17	9	12	16	5	8	4	6	8	3	9	5	6	8	2	1	1	1	1	0	0	0	0	0
	X	COMMERCE	55	15	8	12	15	5	7	4	6	7	2	8	4	6	8	3	1	1	1	0	0	0	0	0	0
	XI	IT	59	17	9	12	16	5	9	4	6	8	3	8	5	6	8	2	1	1	1	1	0	0	0	0	0
4	Trained Graduate Teacher																										
	I	ENGLISH	121	33	19	25	32	12	16	10	13	16	6	17	9	12	16	6	2	2	2	1	3	2	3	3	1
	II	HINDI	118	33	19	24	31	11	16	10	12	15	5	17	9	12	16	6	2	2	2	1	3	2	2	3	1
	III	MATHS	115	31	19	24	30	11	16	9	12	15	6	15	10	12	15	5	2	2	1	2	3	2	2	3	1
	IV	SCIENCE	118	33	19	24	31	11	17	9	12	16	5	16	10	12	15	6	2	2	2	1	3	2	2	3	1
	V	SOCIAL STUDIES	118	33	19	24	31	11	17	9	12	16	5	16	10	12	15	6	2	2	2	1	3	2	2	3	1
Total			1279	358	201	263	340	117	182	100	135	173	58	176	101	128	167	59	22	16	21	10	15	10	11	15	5

अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे नवीनतम जानकारी के लिए राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (नेशनल टेस्टिंग एजेन्सी) (https://recruitment.nta.nic.in) की आधिकारिक वेबसाइट का अवलोकन करते रहें।

हस्ता–
आयुक्त,
जनजातीय छात्रों के लिए राष्ट्रीय शिक्षा समिति (NESTS)

DAVP 43107/11/0007/2122

Badri Gautam

प्रदेश में न्यायालयीन ग्रीष्म अवकाश अब 10 मई से चार जून तक

जागरण, जबलपुर। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने कोरोना संकट को देखते हुए राज्य की अदालतों में ग्रीष्म अवकाश की समयावधि में बदलाव कर दिया है। इसके तहत अब मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय व अधीनस्थ अदालतों में 10 मई से चार जून तक ग्रीष्मकालीन अवकाश लागू रहेगा। पूर्व निर्धारित कैलेंडर के तहत 17 मई से 11 जून तक ग्रीष्मकालीन अवकाश होना था लेकिन मई माह के मध्य में कोविड संकट के अधिक विकराल रूप ले सकने की आशंका को देखते हुए ग्रीष्मावकाश समयावधि में बदलाव कर दिया है। मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद रफीक के आदेश पर रजिस्ट्रार जनरल राजेंद्र कुमार वानी ने इस संबंध में विधिवत अधिसूचना जारी कर दी है। इसमें स्पष्ट किया है कि ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद 10 व 11 जून को कार्यदिवस रहेगा। उल्लेखनीय है कि हाईकोर्ट बार तथा एडवोकेट्स बार के सचिव मनीष तिवारी और हरप्रीत सिंह रूपराह ने ग्रीष्मकालीन अवकाश समय से पूर्व लागू किए जाने की मांग को लेकर मुख्य न्यायाधीश को पत्र सौंपा था।

Badri Gautam